जिले का नाम	31-10-97 तक निर्मित आवासों की संख्या (संख्या में)
राजनंदगांव	937
रतलाम	1336
रीवा	843
सागर	1206
सतना	777
सिवनी	166
शहडौल	3012
शाजापुर	642
शिवहर	209
शिवपुरी	91
सिधी	2530
सरगुजा	5810
टिकमगढ़	611
उज्जैन	962
विदिशा	626
पश्चिम निमाड़	2708
कुल	58214

गरीबी-उन्मूलन

3946. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करने के लिए बेरोजगारी दूर करना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस समय अनेकों योजनाएं चलायी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सभी योजनाओं में परस्पर तालमेल न होने से उनका लाभ वांछित लोगों को नहीं मिल पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु भविष्य में क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार किया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए आबंटित धनराशियां

3947. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महराष्ट्र को 1997-98 में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई और इसमें से कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) 1996-97 और 1997-98 में महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कितने लोग गरीबी-रेखा से नीचे आंके गए थे जिसके आधार पर उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों को केन्द्रीय अंश देश के कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य,/संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों की संख्या में अनुपात में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 1993-94 के सर्वेक्षण (एन०एस०एस०ओ०—43 वो दौर) के आधार पर योजना आयोग द्वारा किया गया गरीबी आकलन इस प्रयोजन के लिए लागू था। इस आकलन के अनुसार महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबों की जनसंख्या 166.90 लाख थी जो कि देश के कुल ग्रामीण गरीबों का 8.52% था।

राज्य से जिलों को आबंटन राज्य की कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की तुलना में जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात तथा जिले में कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन के व्यत्क्रमानुपात के आधार पर बनायी गई पिछड़ेपन की सूची से किए जाते हैं।

1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई तथा उपयोग की गई निधियों के जिला-वार ब्यौरे तथा पिछड़ेपन की सूची जो 1996-97 और 1997-98 के दौरान लागू थी, अनुबंध में है। **[देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं०]**